The two districts have been selected as industrially backward districts.

The level of development of the two districts in different sectors thus is uneven and they are amongst the backward districts in the country.

(c) Special programmes are being prepared under the Fifth Plan in respect of areas having more than 50 per cent tribal concentration. An integrated approach to planning is being adopted so as to ensure faster pace of economic growth in these areas.

Programmes in Manipuri from A.I.R., Silchar

1710. SHRI NOORUL HUDA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether programmes in Manipuri (Meithei) and Bishnupriya Manipuri languages have been introduced in A.I.R., Silchar, as scheduled in October, 1975;

(b) time allotted for each of the languages; and

(c) whether news (local) services have been introduced in Silchar A.I.R.?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): (a) and (b). A daily 30 minute programme in Manipuri and a 15-minute programme in Bishnupriya is proposed to be introduced from A.I.R. Silchar shortly, after the new studios there are commissioned into service.

(c) At present, AIR Silchar broadcasts a 5-minute news bulletin in Dimasa dialect at 5.55 P.M. daily.

Tractor Factory in Madhya Pradesh

1711. SHRI G. C. DIXIT: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there is a scheme for setting up a tractor factory in Madhya Pradesh in the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा पूर्वी राज्यों में बिजली की कमी

1712. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा देश के पूर्वी राज्यों को ऊर्जा की विकट कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उपमन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). हरियाणा में और पूर्व क्षेत्र के बिहार और उड़ीसा राज्यों में विद्युत की कमी नहीं है । मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अधिकतम मांग पर पाबन्दियां लागू हैं ।

मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस समय कई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं । साथ ही समस्त देश में विद्युत की उपलब्धता में और सुधार करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे उपयुक्त किस्म के कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था करके वर्तमान ताप-विद्युत उत्पादन क्षमता से अधिकतम विद्युत का उत्पादन, अतिरिक्त पुर्जों को समय पर

उपलब्ध करने की व्यवस्था, रख-रखाव प्रक्रिया का आधुनिकीकरण, भारों को रोस्टर करना और भिन्न-भिन्न समय करना, प्रणालियों का एकीकृत प्रचालन, निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने का प्रयास, प्रचालन का निर्देशन और ताप-विद्युत केन्द्रों का रख-रखाव, कमी वाले क्षेत्रों के लिए पड़ौसी राज्यों/व्यवस्थाओं से सहायता का प्रबन्ध आदि ।

मध्य प्रदेश के गाँवों में ग्रामीण विद्युतीकरण

1713. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वर्ष 1975–76 और 1976–77 में मध्य प्रदेश में कितनी योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाएगा, और

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उपमन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाया जाता है और वेही इसे कार्यान्वित करते हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक ऋण सहायता देता है । निगम स्वयं किसी योजना को कार्यान्वित नहीं करता ।

1975–76 के दौरान इस निगम ने मध्य प्रदेश की 39 ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं (जिनमें एक ग्राम विद्युत सहकारी योजना भी सम्मिलित है) स्वीकृत की है । इनके लिए ऋण सहायता की कुल राशि 14.81 करोड रुपये है । निगम द्वारा स्वीकृत की गयी योजनाएं चरणबद्ध रूप में 5 वर्ष तक की अवधि में पूरी की जानी है और इन पर कार्य अभी शुरू नही हुआ है ।

1976–77 के दौरान ऋण सहायता की स्वीकृति राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित की गई और उक्त निगम द्वारा अपने निर्धारित मानदण्डो और मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अनुसार अनुमोदित की गयी ग्राम विद्युतीकरण की स्कीमों की संख्या पर निर्भर होगी ।

Allocation for Tribal Sub-Plans prepared by States

1714 PROF NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has approved the Tribal Sub-Plans prepared by the State Governments including the Government of Himachal Pradesh for the development of tribal areas, and

(b) if so, the amount of allocation for each one of the Tribal Sub-Plans prepared by the State Governments?